



# गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल्स (जीसीटी): भारत के लॉजिस्टिक्स परिवर्तन को दे रही गति

14 जनवरी, 2026

## मुख्य बिंदु

- भारतीय रेलवे ने 306 जीसीटी को मंजूरी दी है, जिनकी संयुक्त क्षमता 192 मिलियन टन प्रति वर्ष है; 118 जीसीटी पहले ही कमीशन हो चुके हैं।
- 2014 से अब तक, 2,672 मिलियन टन माल सड़क से रेल पर स्थानांतरित हुआ है, जिससे 143.3 मिलियन टन CO<sub>2</sub> उत्सर्जन में कमी आई।
- जीसीटी नीति के तहत लगभग ₹8,600 करोड़ का निजी निवेश जुटाया गया है।
- जीसीटी से माल ढुलाई राजस्व 2022-23 और 2024-25 के बीच चार गुना बढ़कर ₹12,608 करोड़ हो गया।

## परिचय

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है जिसमें लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 7.97% तक कम कर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया है। यह उपलब्धि निरंतर सुधारों और एकीकृत नियोजन की सफलता को दर्शाती है, जो राष्ट्र को वैश्विक मानदंडों के करीब ले जा रही है। यह दर्शाता है कि समन्वित अवसंरचना विकास और डिजिटल एकीकरण कैसे लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और भविष्य के लिए तैयार बनाये जा रहे हैं।

इस परिवर्तन का केंद्र पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जिसने रेलवे, राजमार्ग, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को एक एकीकृत ढांचे में एक साथ ला दिया है। निर्बाध मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी सक्षम करके, यह योजना उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने, ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया जैसे प्रयासों का समर्थन करने तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

**गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)** इस दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ हैं, जो आधुनिक लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान कर रहे हैं और भारत को वैश्विक व्यापार केंद्र के रूप में मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं।

## गति शक्ति कार्गो टर्मिनल

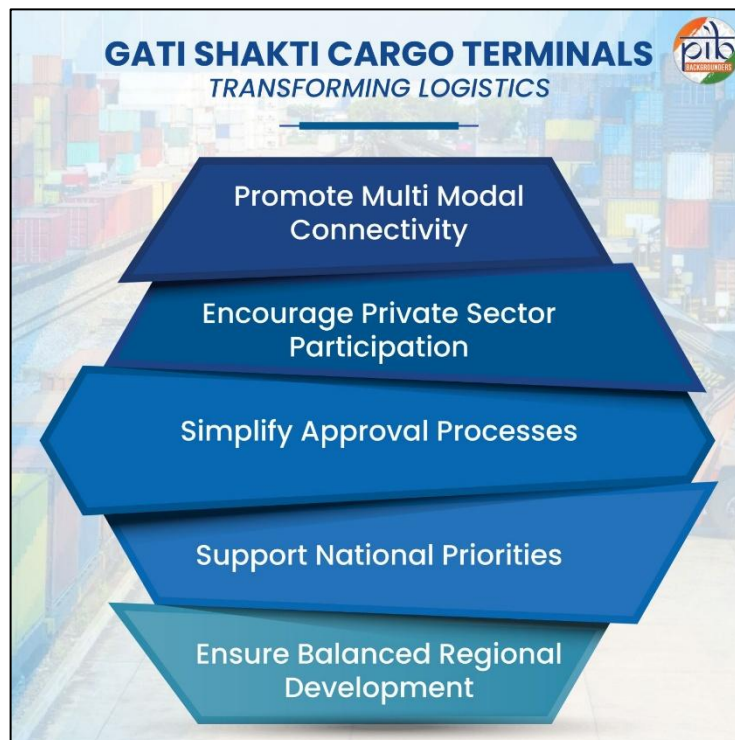
रेलवे कार्गो टर्मिनल एक ऐसी सुविधा है जहाँ माल को लोड, अनलोड किया जाता है और ट्रेनों तथा अन्य परिवहन साधनों के बीच स्थानांतरित किया जाता है। यह लॉजिस्टिक्स चेन में एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो कंटेनरों और थोक माल दोनों के कुशल संचालन को सुगम बनाता है। पहले, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जैसे मल्टीमॉडल हबों के अभाव में भारत में माल ढुलाई सड़क, रेल और बंदरगाहों पर बिखरी रहा करती थी, जिससे विलंब, उच्च लागत और भीड़भाड़ की समस्या उत्पन्न होती थी। एकीकृत हबों की आवश्यकता इन साधनों को जोड़ने, माल हैंडलिंग को तेज करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए है।

**गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल (जीसीटी)** रेल मंत्रालय की 2021 की जीसीटी नीति के तहत विकसित और स्थापित किए जा रहे आधुनिक कार्गो टर्मिनल हैं, जो रेल को अन्य परिवहन साधनों के साथ एकीकृत करते हैं।

जीसीटी को 'इंजन ऑन लोड' (ईओएल) संचालन के साथ विकसित किया जा रहा है ताकि रुकावट को न्यूनतम किया जा सके और रेलवे अवसंरचना का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो। इनमें आधुनिक माल हैंडलिंग सुविधाएँ जैसे मैकेनाइज्ड लोडिंग सिस्टम और साइलो उपलब्ध हैं, जो हैंडलिंग समय को काफी कम कर देते हैं। इसका समग्र उद्देश्य भारतीय रेलवे के कुल माल ढुलाई में हिस्सेदारी बढ़ाना है, जिसमें तेज, कुशल और विश्वसनीय माल ढुलाई सेवाएँ प्रदान करना संभव हो सके। यह आवश्यक है क्योंकि रेल परिवहन सड़क परिवहन की तुलना में अधिक ऊर्जा-कुशल, लागत-प्रभावी और बहुत कम कार्बन उत्सर्जन पैदा करता है, जो भारत को लॉजिस्टिक्स लागत कम करने और अपनी स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है। रेलवे का खर्च अनुमत मुफ्त समय के भीतर रखा जाता है, ताकि प्रक्रिया पूरी होते ही ट्रेन तुरंत प्रस्थान कर सके।

*ईओएल प्रणाली के तहत, लोकोमोटिव लोडिंग या अनलोडिंग के दौरान टर्मिनल पर ही रहता है, अनुमत मुफ्त समय के भीतर रेलवे के खर्च पर प्रतीक्षा करता है, ताकि प्रक्रिया पूरी होते ही ट्रेन तुरंत प्रस्थान कर सके।*

कार्गो टर्मिनल भारत के लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के रणनीतिक केंद्र हैं। इनका डिज़ाइन निर्बाध कनेक्टिविटी, निजी भागीदारी और सरलीकृत प्रक्रियाओं पर केंद्रित है, जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और संतुलित क्षेत्रीय विकास के साथ संयोजित है।



- गति शक्ति कार्गो टर्मिनल मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जो रेलवे को सड़कों, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के साथ निर्बाध रूप से जोड़ते हैं।
- इनके विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करके, ये टर्मिनल क्षमता का विस्तार करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं।
- जीसीटी परियोजनाओं के अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है, जिसमें समयबद्ध मंजूरी सुनिश्चित करके तेजी से कार्यान्वयन होता है।
- यह पहल राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है, जो ईज ऑफ़ डूइंग बिजनेस, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का समर्थन करती है।
- टर्मिनल स्थानों का चयन देश के विभिन्न राज्यों में किया जा रहा है, जो देश में एक संतुलित क्षेत्रीय विकास और समावेशी वृद्धि सुनिश्चित करता है।

### गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल नीति 2021

भारतीय रेल द्वारा 15 दिसंबर 2021 को शुरू की गई इस नीति का उद्देश्य आधुनिक कार्गो टर्मिनलों के विकास को गति प्रदान करना, मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करना और भारत के माल परिवहन के समस्त परिदृश्य को मजबूत बनाना था। इसका उद्देश्य समूची प्रक्रिया को सुचारु बनाना, निजी निवेश को प्रोत्साहित करना और

उद्योग की बढ़ती मांग के मुताबिक बुनियादी संरचना पर बल देना और कुल मिलाकर भारत को लॉजिस्टिक सुविधाओं का वैश्विक केंद्र बनाना है।

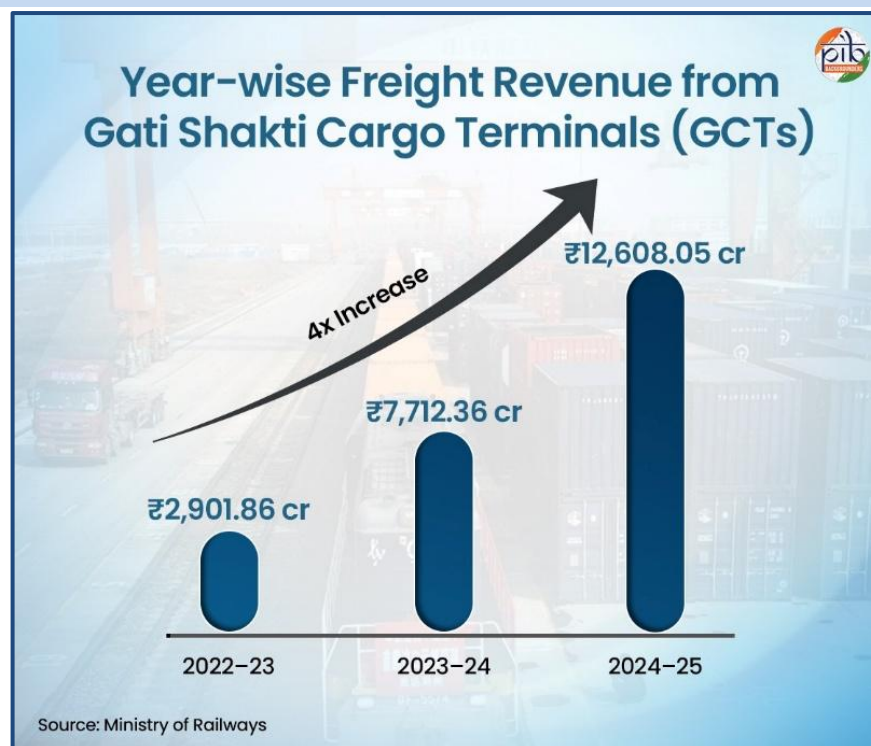
- **लागत में छूट-** विभागीय शुल्क, भूमि लाइसेंसिंग शुल्क और व्यावसायिक कर्मचारी शुल्क की माफ़ी
- **समर्थन सुविधाएं-** रेलवे अपने हर मॉल सेवा स्टेशनों के सामान्य उपयोग स्थलों पर ट्रेफिक सुविधा का निर्माण और रखरखाव तथा संचालन करती है
- **माल ढुलाई में छूट-** मध्य-खण्ड ब्लॉक हट / ब्लॉक स्टेशन टर्मिनल पर दस लाख टन या उससे अधिक की माल ढुलाई और उसकी बहिर्निकासी पर दस प्रतिशत की छूट।
- **परिसंपत्ति का रखरखाव-** रेलवे, यार्ड और लोडिंग/अनलोडिंग लाइनों के अलावा ट्रैक, सिग्नलिंग और ओवरहेड उपकरण का रखरखाव शामिल करता है।
- **कनेक्टिविटी अधिकार-** जरूरत पड़ने पर रेलवे अतिरिक्त टर्मिनलों से अपने ट्रैक से कनेक्टिविटी बना सकती है।
- **व्यावसायिक भूमि उपयोग-** रेलवे अपनी अधिशेष भूमि का रेल भूमि विकास प्राधिकरण के प्रावधानों के तहत अपने उपयोग में इस्तेमाल कर सकता है।
- **रणनीतिक महत्व-** एक निर्बाध मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक परिदृश्य का निर्माण जिससे किसी तरह की रुकावट की समाप्ति, कारोबार में बढ़ोतरी और दीर्घकालिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा की क्षमता में बढ़ोतरी

## अब तक हासिल की गई प्रगति

गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अपने प्रक्षेपण के बाद से एक विजन से वास्तविकता बनने के सफर तक पहुँच चुके हैं, जो अपनी प्रक्रिया के तहत पहले स्वीकृतियों, नई सुविधाओं के कमीशनिंग और माल हैंडलिंग क्षमता के व्यापक लाभों में परिवर्तित हो रहे हैं।

- **स्वीकृतियाँ और कमीशनिंग:** भारतीय रेलवे ने 306 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल (जीसीटी) के प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनमें से 118 पहले ही कमीशन हो चुके हैं, जो कार्यान्वयन में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।
- **कमीशन किए गए टर्मिनल और क्षमता:** 118 कमीशन किए गए टर्मिनलों की अनुमानित संयुक्त ट्रेफिक हैंडलिंग क्षमता 192 मिलियन टन प्रति वर्ष है, जो लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और रेल माल ढुलाई में उल्लेखनीय वृद्धि में योगदान दे रही है।

- **निजी निवेश:** जीसीटी नीति की शुरुआत के बाद से लगभग ₹8,600 करोड़ का निजी निवेश जुटाया गया है, जो उद्योग की मजबूत भागीदारी और सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल की सफलता को रेखांकित करता है।
- रेलवे बोर्ड द्वारा जारी **जीसीटी पर मास्टर सर्कुलर (2022)** कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करता है, जिसमें समझौते, संचालन मानक और इन टर्मिनलों की दक्षता बढ़ाने के लिए संशोधन शामिल हैं।
- **लागत-प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल:** रेलवे एक स्वच्छ और अधिक कुशल परिवहन साधन है, जिसकी लागत सड़क परिवहन से आधी से भी कम है और कार्बन उत्सर्जन लगभग 90% कम है। सड़क से रेल पर माल ढुलाई स्थानांतरित करने से भीड़भाड़ कम होती है और भारत के डीकार्बनाइजेशन लक्ष्यों का समर्थन होता है। 2014 से, इस स्थानांतरण से अतिरिक्त 2,672 मिलियन टन माल रेल पर आ गया है, जिससे 143.3 मिलियन टन CO<sub>2</sub> उत्सर्जन की बचत हुई है।
- जीसीटी नीति के प्रावधानों के अनुरूप, मंजूरी प्राप्त एजेंसियों को **24 महीनों** के भीतर निर्माण पूरा करना आवश्यक है, जो नई टर्मिनलों की समय पर डिलीवरी और संचालन तैयारियों को सुनिश्चित करता है।
- **माल ढुलाई राजस्व:** गति शक्ति कार्गो टर्मिनल ने मजबूत प्रदर्शन दिखाया है, जिसमें 2022-23 और 2024-25 के बीच माल ढुलाई राजस्व चार गुना से अधिक बढ़ गया, जो भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उनकी बढ़ती भूमिका को रेखांकित करता है।



गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति के ठोस परिणाम स्वीकृतियों, कमीशनिंग और माल ढुलाई राजस्व में सतत वृद्धि इस बात को दर्शाती है कि गति शक्ति कार्गो टर्मिनल नीति ठोस परिणाम दे रही है। इसने रेल लॉजिस्टिक्स को मजबूत किया है, निजी निवेश को आकर्षित किया है और भारतीय रेलवे को कुशल माल ढुलाई के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित किया है।

## लॉजिस्टिक्स विकास को गति देने वाले प्रमुख गति शक्ति कार्गो टर्मिनल

लॉजिस्टिक्स परिदृश्य का परिवर्तन किसी एक टर्मिनल द्वारा नहीं, बल्कि नवीनतम संचालित जीसीटी नेटवर्क द्वारा संचालित हो रहा है। इस प्रभाव को कई प्रमुख उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

- ❖ **मानेसर (हरियाणा) जीसीटी-** देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी-मॉडल कार्गो टर्मिनल हरियाणा के मानेसर स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के प्लांट पर स्थित है। 46 एकड़ में फैला यह टर्मिनल चार पूर्ण लंबाई वाले रेक हैंडलिंग लाइनों और एक इंजन एस्केप लाइन वाली पूर्ण विद्युतीकृत कॉरिडोर से सुसज्जित है, जिसकी कुल ट्रैक लंबाई 8.2 किमी है। यह पटली रेलवे स्टेशन से 10 किमी लंबे समर्पित रेल लिंक से जुड़ा है, जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसकी लागत ₹800 करोड़ आई है जिसमें ₹684 करोड़ हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एचआरआईडीसी) द्वारा वित्त पोषित हैं और शेष मारुति सुजुकी द्वारा। लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया यह टर्मिनल भारत में सबसे अधिक लोडिंग क्षमताओं में से एक है, जो प्रतिवर्ष 4.5 लाख ऑटोमोबाइल हैंडल करने में सक्षम है।
- ❖ **उत्तर-पूर्व के टर्मिनल-** असम के मोइनारबंद और सिनामारा गति शक्ति कार्गो टर्मिनल उत्तर-पूर्व के लॉजिस्टिक्स को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो कोयला, कंटेनर, खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पादों, ऑटोमोबाइल और सामान्य माल के विविध मिश्रण को हैंडल करते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे (एनएफआर) के तहत विकसित मोइनारबंद विशेष रूप से पेट्रोलियम और तेल परिवहन से जुड़ा है, खासकर इंडियन ऑयल (आईओएमबी) उत्पादों के साथ। जबकि सिनामारा भी एनएफआर के तहत विकसित है और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एफसीआई) साइडिंग के माध्यम से खाद्यान्न तथा उर्वरकों से जुड़ा है। ये मल्टीमॉडल हब क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाते हैं, उद्योगों और कृषि उत्पादकों को व्यापक बाजारों से जोड़ते हैं तथा पीएम गति शक्ति पहल का समर्थन करते हैं, जिसमें एकीकृत रेल, सड़क और जलमार्ग परिवहन के माध्यम से दक्षता बढ़ाना और लागत कम करना

शामिल है। इस आधार पर, असम में **छह नए कार्गो टर्मिनल** निर्माणाधीन हैं, जिसमें **बाइहाटा टर्मिनल** पूर्ण होने वाला है। हाबाइपुर, जोगीघोपा, केन्दुकोना, बसुगांव और चायागांव में आगामी सुविधाएँ राज्य के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को और विस्तार देंगी, लागत कम करेंगी तथा पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत उत्तर-पूर्व में मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को व्यापक बनाएंगी।

- ❖ **गुजरात का न्यू संजाली जीसीटी-** गुजरात का न्यू संजाली गति शक्ति कार्गो टर्मिनल गति शक्ति नीति के तहत निजी भूमि पर निर्मित पहली सुविधा है, जो **वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर** के साथ स्थित है। यह आधुनिक टर्मिनल भारत के लॉजिस्टिक्स परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। एक रणनीतिक माल ढुलाई केंद्र के रूप में डिज़ाइन किया गया, यह उच्च गति, उच्च क्षमता वाले माल परिवहन का समर्थन करेगा, मल्टीमॉडल एकीकरण को बढ़ावा देगा तथा हरित, अधिक कुशल लॉजिस्टिक्स संचालन को आगे बढ़ाएगा।

## आगामी कार्य

आने वाले समय में, जीसीटी नीति एक **विश्वस्तरीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क** की कल्पना करती है जो डिजिटल रूप से एकीकृत, उद्योग-प्रतिक्रियाशील और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी हो। इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल हैं:

- टर्मिनल विकास को तेज करने के लिए **निजी भागीदारी का विस्तार**।
- उद्योग मांग और क्षेत्रीय विकास पैटर्न के आधार पर **नए जीसीटी स्थानों की निरंतर पहचान**।
- गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से **डिजिटल एकीकरण** को मजबूत करना, जो वास्तविक समय ट्रेकिंग और भविष्यवाणी विश्लेषण को सक्षम बनाए।
- लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के एकल अंक के हिस्से के रूप में हासिल करने की उपलब्धि पर आधारित, भारत को वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करने का **दीर्घकालिक दृष्टिकोण**, तथा हरित परिवहन समाधानों के माध्यम से स्थिरता को आगे बढ़ाना।



## निष्कर्ष:

गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। अवसंरचना विकास को डिजिटल एकीकरण और निजी भागीदारी के साथ जोड़कर, ये टर्मिनल लंबे समय से चली आ रही माल परिवहन की अक्षमताओं का समाधान करते हैं तथा राष्ट्रीय आर्थिक लक्ष्यों के साथ संयोजित होते हैं। कार्यान्वयन के आगे बढ़ने के साथ, जीसीटी भारत के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य को परिवर्तित करने के लिए इसे अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी बनाते हुए और भविष्य के लिए तैयार है।

## संदर्भ:

### रेल मंत्रालय:

<https://x.com/RailMinIndia/status/1991332583255478424>

[https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU671\\_cWHwfg.pdf?source=pqals](https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/186/AU671_cWHwfg.pdf?source=pqals)

[https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2967\\_ie0VNH.pdf?source=pqals](https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2967_ie0VNH.pdf?source=pqals)

<https://www.pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1814049&reg=3&lang=2>

[https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic\\_comm/Freight\\_Marketing\\_2022/GCT%20-2022.pdf](https://indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Marketing_2022/GCT%20-2022.pdf)

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2136909&reg=3&lang=2>

<https://www.facebook.com/NRIyIndia/posts/sustainable-transport-boost-100th-rake-rolls-out-from-msil-manesarthis-achieveme/1269089571924456/>

[https://nfr.indianrailways.gov.in/view\\_detail.jsp?lang=0&dcd=2908&id=0,4,268](https://nfr.indianrailways.gov.in/view_detail.jsp?lang=0&dcd=2908&id=0,4,268)

[https://x.com/dfccil\\_india/status/1942872988933673181](https://x.com/dfccil_india/status/1942872988933673181)

पीआईबी शोध

पीके/केसी/एमएम